The Indian Express- 06- November-2022

It's time to end all inter-state water disputes, says Dhankhar

EXPRESS NEWS SERVICE
NEW DELHI, NOVEMBER 5

OBSERVING THAT inter-state water disputes are in favour of none and go against the interest of the country, Vice President Jagdeep Dhankhar said on Saturday that the time has come to take proactive initiatives to resolve these disputes.

Addressing the valedictory session of the 7th India Water Week organised at Greater Noida, Dhankhar expressed hope to see some "positive results" in this direction. When Dhankhar made these remarks, Agriculture Minister Narendra Singh Tomar and Jal Shakti Minister Gajendra Singh Shekhwat were also present on the dais.

"With the presence of two very senior ministers and particularly Narendra Singh ji Tomar, for whom all of us have very high regard, I will appeal to him that in the true spirit of federalism, time has come now that we take proactive initiatives to resolve inter-state water disputes. These disputes are in favour of none and go against the very interest of the country and the people at large. I

Vice President Jagdeep Dhankhar

am sure, with the sagacious approach and the experience he brings on the table, I expect positive results," Dhankhar said.

Dhankhar also urged people to make judicious use of resources. "Consumption of natural resources including water, electricity, gas and energy cannot be done merely on the basis of economic strength. We cannot exploit these resources on the plank that we can afford (them)," he said.

Dhankhar highlighted that equitable distribution of natural resources is the fundamental spirit of the Indian Constitution.

Addressing the gathering earlier, Tomar said the agriculture sector consumes most water but at a time of climate change, it is necessary to know how to manage water.

He said there is a need to run a big campaign for this.

Tomar said, all should join hands for "Save Water - Save Life Campaign" then only this goal can be achieved.

Shekhawat said India has emerged as the role model for the developing countries.

In her address, Debashree Mukherjee, Special Secretary, Ministry of Jal Shakti, said that this has been the largest edition of the India Water Week. The delegates from 28 countries participated in the 7th India Water Week and more than 200 papers were presented, she informed.

Deccan Chronicle- 06- November-2022

INTER-STATE WATER DISPUTES FAVOUR NONE: VP

New Delhi, Nov. 5: The time has come to take proactive steps to resolve all inter-state water disputes as these favour none and are against the interest of the country and people at large, Vice President Jagdeep Dhankhar said on Saturday.

He also reminded people that natural resources such as water and fuel should not be wasted as the country can ill afford to do so.

Addressing the valedictory function of the 7th India Water Week in Greater Noida, Dhankhar stressed the need to rejuvenate water bodies.

"In the true spirit of federalism, the time has come now that we take proactive initiatives to resolve inter-state water disputes," he said underling that these disputes are "in favour of none" and go against the interest of the country and people at large.

Hindustan- 06- November-2022

ग्रेटर नोएडा के एक्सपो मार्ट में चल रहे भारत जल सप्ताह के दौरान जल शोधन और जल को बचाने के लिए गंभीरता से चर्चा हुई

देश में सिर्फ पांच फीसदी जल का ही पुनः इस्तेमाल

7th IWW 2022 भारत जल सप्ताह

■ निशांत कौशिक

नोएडा। भारत में सिर्फ पांच प्रतिशत पानी का ही शोधन कर पुनः इस्तेमाल किया जाता है। वहीं विश्व में सर्वाधिक 90 प्रतिशत पानी का शोधन कर उसे पुनः इस्तेमाल कर इजरायल दुनिया में पहले नंबर पर है।

पानी का शोधन कर उसे फिर से इस्तेमाल करने के मामले में दूसरे नंबर पर सिंगापुर है, जो 30 प्रतिशत तक पुनः पानी का इस्तेमाल करता है। ग्रेटर नोएडा के एक्सपो मार्ट में भारत जल सप्ताह के दौरान नीति आयोग की रिपोर्ट पर हुई चर्चा के दौरान ये तथ्य सामने आए हैं। जल विशेषज्ञ और आईआईटिएन डॉक्टर दिनेश पोसवाल और नीर फाउंडेशन के संस्थापक रमनकांत त्यागी के अनुसार देश में पानी का दोहन खूब हो रहा है, लेकिन पानी का शोधन कर उसे फिर से इस्तेमाल करने के मामले में हम काफी पीछे हैं।

इजरायल में 60 प्रतिशत रेगिस्तान है। वहां पर पानी की कमी है। वहां पानी का एक बार इस्तेमाल करने के बाद शोधन कर उसे उद्योगों और खेती में इस्तेमाल किया जाता है। विशेषज्ञों के अनुसार भारत में इजरायल के मुकाबले साढ़े सात गुना अधिक पानी का इस्तेमाल होता है। इजरायल ने संसाधनों का अच्छा प्रबंधन कर पानी का पुनः इस्तेमाल किया है। भारत को दस से 15 सालों में ऐसी तकनीकों का प्रयोग करना होगा, जिससे 80 से 85 प्रतिशत पानी का शोधन कर उसे पुनः इस्तेमाल किया जा सके। इसे लेकर जल सप्ताह में भी मंथन हुआ है। इसके लिए विश्व बैंक सहायता राशि को भी बढ़ाने के लिए तैयार है। वर्तमान में करीब 10 हजार करोड़ की आर्थिक सहायता विश्व बैंक से मिल रही है। 2040 तक इसे 30 हजार करोड़ करने की बात विश्व बैंक ने कही है।

ग्रेटर नोएडा में चल रहे भारत जल सप्ताह-2022 के समापन समारोह को संबोधित करते उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। ● हिन्दुस्तान

70 प्रतिशत भूजल देश में है प्रदूषित

90 फीसदी पानी का शोधन कर इस्तेमाल करता है इजरायल

विवादों से बचें राज्य : उपराष्ट्रपति

ग्रेटर नोएडा, वरिष्ठ संवाददाता। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि राज्यों को जल विवादों से बचना चाहिए। इनका हल निकलना चाहिए। इससे किसी को फायदा नहीं होगा।

उपराष्ट्रपति ने कहा कि पानी समेत ऊर्जा के अन्य संसाधनों का उपयोग आर्थिक क्षमता के आधार पर नहीं होना चाहिए। पानी की बूंद-बूंद बचानी जरूरी है। हमारी संस्कृति भी जल की बात करती है। ऋग्वेद में कहा गया है कि जल ही अमृत है। भारतीय संस्कृति में जोहड़ का बहुत महत्व है। उन्होंने कहा कि यह वाटर वीक का समापन नहीं है बल्कि नए संकल्प की शुरुआत है। स्वच्छ भारत अभियान ने देश को नई दिशा दिखाई है। उपराष्ट्रपति ने शनिवार को ग्रेटर नोएडा के एक्सपो मार्ट में चल रहे इंडिया वाटर वीक के समापन समारोह में शिरकत की।

कम होते तालाबों पर गंभीरता से काम हो : शेखावत

एक्सपो मार्ट में केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि जनसंख्या और जल की उपलब्धता में विषमता पर गंभीरता से विचार होना चाहिए। उन्होंने इंडिया वाटर वीक में आई सिफारिशों को आगे बढ़ाने की अपील की और सभी से इस पर अमल करने के लिए कहा।

यहां भूजल की पहली परत पीने योग्य नहीं

छोटी नदियों में पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं

वर्ष 2018 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण विभाग ने देश में नदियों के 351 ऐसे स्थान चिह्नित किए हैं, जहां जलप्रदूषण सर्वाधिक है। इसके अलावा गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु और नर्मदा जैसी कुछ बड़ी नदियों को छोड़कर शहरों के बीच से होकर बहने वाली किसी भी छोटी नदी में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं बची है। इन नदियों में रहने वाले जलीय जीव भी लगभग समाप्त हो चुके हैं।

28 छोटी नदियां प्रदूषित

पिछले कई सालों से जल संरक्षण, छोटी और स्थानीय नदियों के अस्तित्व को बचाए रखने के लिए संघर्ष कर रहे रमन त्यागी ने कहा कि गंगा और यमुना के दोआब में पानी का प्रदूषण बड़ी समस्या है। यहां से होकर 28 छोटी नदियां निकलती हैं और यह सभी प्रदूषित हैं। इन नदियों के प्रदूषण के लिए 80 प्रतिशत शहर से निकलने वाला सीवरेज और 20 प्रतिशत औद्योगिक कचरा जिम्मेदार है। औद्योगिक कचरे में रसायन होने की वजह से वह अधिक खतरनाक है।

गौतमबुद्ध नगर में भूजल संसाधनों की स्थिति

विकास खंड का नाम	भौगोलिक क्षेत्र	भूजल रिचार्ज	वार्षिक भूजल दोहन
बिसरख	33476	7735.62	9095.85
दादरी	22718	13033.16	10498.28
दनकौर	43776	13908.00	11822.61
जेवर	36827	11142.97	11227.48

नोटः भौगोलिक क्षेत्र हेक्टेयर में। दोहन और रिचार्ज हेक्टेयर मीटर में

Amar Ujala- 06- November-2022

अंतरराज्यीय जल विवादों से बचें राज्य : धनखड़

इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में 7वें इंडिया वाटर वीक-2022 के समापन पर बोले उपराष्ट्रपति

अमर उजाला ब्यूरो

ग्रेटर नोएडा। इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में शनिवार को सातवें इंडिया वाटर वीक-2022 के समापन पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा, राज्यों को अंतरराज्यीय जल विवादों से बचते हुए हल निकलना चाहिए। उपराष्ट्रपति ने वाटर वीक में जल शक्ति मंत्रालय, भारत और विदेश के प्रतिनिधियों के प्रयासों की सराहना की।

स्वच्छ भारत अभियान की तारीफ करते हुए धनखड़ ने कहा इससे देश की महिलाओं के सम्मान के रक्षा हुई। सभी को ऊर्जा और प्राकृतिक संसाधनों का बराबर उपयोग करने का हक है। संसाधनों का समुचित उपयोग करने आदत बनानी होगी, जिससे जल की बर्बादी न हो। इस मौके पर जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि यह संकल्प लेने का समय है कि जल संरक्षण के लिए हम कुछ करें। जनसंख्या और जल की उपलब्धता में विषमता पर गंभीरता से विचार हो। उन्होंने खेती में नवाचार 'पर ड्रॉप मोर ड्रॉप' का नारा दिया। वाटर वीक-2022 को सफल बताते हुए उन्होंने कहा कि इसमें 2000 प्रतिभागी और 28 देशों के विशेषज्ञ प्रतिनिधियों ने हिस्सा लेकर जल प्रबंधन और आवश्यकता पर गहन विचार किया।

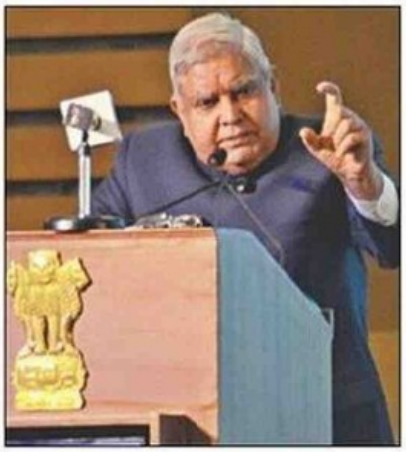

लोगों को संबोधित करते उपराष्ट्रपति।

'सिंचाई में तकनीक का उपयोग जरूरी'

कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा कि सिंचाई में टेक्नोलॉजी का उपयोग होना चाहिए। सूक्ष्म सिंचाई परियोजना को बेहतर बताते हुए उन्होंने कहा कि 70 लाख से अधिक लोग इसे अपना चुके हैं। इस तरह के बीजों का ईजाद किया जाए, जिसमें जल का उपयोग कम हो सके। वर्षा आधारित क्षेत्र में जल संचय के लिए शोध और अविष्कार को भी विशेष तरजीह देने की बात कही।